रणजीत टाइम्स

वर्ष : 1, अंक: 135 इंदौर, सोमवार 26 मई 2025

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

DIGITAL EDITION

ऐतिहासिक होगा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, महिला सम्मेलन की कमान खुद महिलाएं संभालेंगी:विष्णुदत्त

रंजीत टाइम्स

भोपाल 1 लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन 31 मई को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में एक भव्य महिला सम्मेलन के साथ होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सम्मेलन की खास बात यह होगी कि इसकी संपूर्ण कमान महिलाओं के हाथ में होगी- मंच संचालन से लेकर क्राउड मैनेजमेंट, यातायात और बैठक व्यवस्था तक सभी जिम्मेदारियां महिला कार्यकर्ता निभाएंगी। शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत मिसाल होगा। उन्होंने कहा, 'सम्मेलन में भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ताओं के साथ जरूर रहेगा, लेकिन उनके पीछे। आगे की भूमिका पूरी तरह से मातृशक्ति के पास होगी।'विष्णु दत्त शर्मा ने इस आयोजन को 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में महिला शक्ति के सामने उपस्थित होंगे, जब देश ने आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता दिखाई है। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक महिलाओं की उपस्थिति वाला यह सम्मेलन देशभर में महिला नेतृत्व की क्षमता का प्रमाण बनेगा। राष्ट्रीय हिंदी मेल से बातचीत में विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, 'देवी अहिल्याबाई होल्कर ने सदियों पहले महेश्वर साड़ी के निर्माण के माध्यम से महिला स्वावलंबन की नींव रखी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।' अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती को लेकर 20 से 31 मई तक इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और अन्य जिलों में विविध सांस्कृतिक व साहित्यिक आयोजन किए जा रहे हैं। इनमें महानाट्य 'अहिल्याकथान संनादति', महिला कवि सम्मेलन, एकल कविता पाठ और 'शिवयोगिनी अहिल्या' जैसे नाटकों का मंचन प्रमुख आकर्षण हैं। 31 मई को भोपाल में आयोजित होने वाला यह महिला सम्मेलन इस समर्पण और जागरूकता का अंतिम और सबसे भव्य पड़ाव होगा। आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति और संबोधन न केवल कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के संकल्प को नई ऊर्जा देगा।

शिवराज सिंह चौहान की 'पदयात्रा' बनी राजनीतिक बहस का केंद्र, कांग्रेस बोली- ये यात्रा अगली पीढ़ी के लिए' भाजपा ने कहा-जनसेवा का अभियान

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में चार बार के मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कभी 'पांव-पांव वाले भैया' के नाम से पहचाने जाने वाले शिवराज सिंह अब 25 मई से एक बार फिर पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त सियासी हलचल मच गई है। जहां भाजपा इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का एक जनसंपर्क अभियान बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे शिवराज की अगली पीढ़ी को सियासी जमीन तैयार करने की कवायद करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान का यह अभियान करीब 25 साल पहले की उस यात्रा की याद दिलाता है, जब वे जमीन से जुड़कर राज्य की राजनीति में सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरे थे। अब जब वे केंद्र में मंत्री हैं और राज्य की राजनीति से औपचारिक रूप से अलग हो चुके हैं, तब उनका फिर से जनता के बीच जाना नए राजनीतिक संकेत दे रहा है। यह यात्रा रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर की होगी, जिसमें वे गांव-गांव जाकर न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, बल्कि सीधे जनता से संवाद भी करेंगे।

कांग्रेस ने इस यात्रा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि यह यात्रा शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक उत्तराधिकार की भूमिका तैयार करने के लिए है। उन्होंने कहा कि शिवराज अब अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और बहू अमानत को आगे लाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि शिवराज को केंद्र में मजबूरन भेजा गया था और अब वे राज्य की राजनीति को अपने परिवार में सुरक्षित करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि विधानसभा उपचुनाव में शिवराज की पारंपरिक सीट बुधनी से उनके परिवार को टिकट नहीं मिला और पार्टी ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाकर विधायक चुना। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह हर जनसेवा अभियान में साजिश की बू सूंघती है। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह की यह पदयात्रा वास्तव में जनता से जुड़ने का प्रयास है। इसमें वे गांवों में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण सड़क और स्वरोजगार जैसी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे और लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। भाजपा का यह भी कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से सरकार की नीतियों का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और जिन स्थानों पर योजनाएं प्रभावी नहीं हैं, वहां संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इसे भाजपा जनसेवा से जोड़ रही है और कह रही है कि शिवराज का यह प्रयास प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास के लिए एक अनुकरणीय कदम होगा। इस पदयात्रा के राजनीतिक मायने इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की पहचान एक जननेता की रही है और अब जब उनके परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, तब इस यात्रा को केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार तक सीमित मानना राजनीतिक रूप से कठिन है। हालांकि भाजपा इसे नकार रही है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस यात्रा से 'वंशवाद' की जमीन तैयार हो रही है।

दर्दनाक हादसा: नींद में थी 10 साल की बच्ची, कच्चे मकान की दीवार गिरने से हुई मौत, रो-रोकर बेहाल परिजन

रणजीत टाइम्स

धार। शुक्रवार की देर रात एक मासूम बच्ची की मौत उस समय हो गई जब वह गहरी नींद में थी। नौगांव थाना क्षेत्र के लसूडिया गांव में कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी और इस हादसे ने एक 10 वर्षीय बच्ची की जान ले ली। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और बच्ची के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मुकेश नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ लंबे समय से लसूड़िया गांव में एक कच्चे मकान में रह रहा था। बीती रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी अचानक मकान की एक पुरानी दीवार गिर गई। इस हादसे की चपेट में आ गई उसकी 10 साल की मासूम बेटी गौरी, जो उस समय बेखबर होकर सो रही थी। दीवार के मलबे में दबने से गौरी को गंभीर चोटें आईं और परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई। सहायक उपनिरीक्षक उमेश सोनगरा ने बताया कि दीवार किसी वजह से गिर गई थी और हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस हृदयविदारक हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर और कमजोर घरों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। बारिश या मौसम में नमी आने के साथ ही कच्चे मकानों की दीवारें ढहने लगती हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक इनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण को लेकर कोई ठोस योजना दिखाई नहीं देती। ऐसे हादसे न केवल मासूम जानों को लील लेते हैं, बल्कि पीछे छूट जाते हैं सिर्फ आँसू और बिखरे हुए सपने। गौरी की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है। गांव के लोग भी इस त्रासदी से स्तब्ध हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस तरह के कच्चे मकानों की जल्द जांच कर उन्हें सुरक्षित बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई और बच्चा ऐसी मौत का शिकार न हो।

सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर लगेगा प्रतिबंध, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी तेज

रंजीत टाइम्स

भोपाल 1 मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। दरअसल शिक्षा विभाग इस वर्ष प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लगातार आरोप लग रहे थे कि करीब 20 हजार शिक्षक स्कूलों में नहीं जाते। खुद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनके ही जिले की कई शिक्षक सालों से स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष ऐसे शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 15 जून से शुरू हो रहे सत्र में ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए नया पोर्टल तैयार कर रहा है। विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 15 जून से यह पोर्टल काम करने लगेगा। हालांकि शिक्षकों का इसमें विरोध भी है

उनका कहना है कि विभाग द्वारा अलग-अलग जगह ड्यूटी लगाई जाती है उस दौरान शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंच पाते ऐसे में उनके अटेंडेंस कैसे लग पाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर शिल्या गुप्ता ने बताया कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 15 जून से शुरू हो रहे सत्र में स्कूलों में शिक्षको की ई-अटेंडेंस शुरू की जाएगी। जब यह तैयारी शुरू हुई थी तो कहा गया था कि पहले से संचालित एम शिक्षा मित्र पर टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। अब विभाग ने निर्णय बदला है। विद्यालयों के समस्त रिकार्ड को संग्रहित करने के लिए विभाग ने जिस नवीन 3.0 पोर्टल को लांच किया है। उसी के माध्यम से शिक्षकों की ई-अटेंडेंस लगवाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है।

1 जून को निःशुल्क स्वास्थ शिविर का आयोजन,, अल्पसंख्याक योजना एवम जीवन प्रकाश योजना की जानकारी भी दी जाएगी

रंजीत टाइम्स

इंदौर 1 श्री धर्मदास कृष्णा स्मृति सुकृत ट्रस्ट एवं राजमोहल्ला जैन श्री संघ इंदौर के तत्वाधान मे अरबिंदो हॉस्पिटल के सहयोग से मालवा के गौरव, सौभाग्य कुल दिवाकर श्रमण संघीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के 51 वे दीक्षा दिवस के उपलक्ष मे 1 जून रविवार को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मप्र के समग्र जैन समाज के लिए निःशुल्क स्वास्थ शिविर जैन स्थानक भवन, साउथ राजमोहल्ला इंदौर पर आयोजित किया जा रहा है । मप्र जैन कॉन्फ्रेंस के अल्पसंख्यांक योजना के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बागमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में कैंसर, हड्डी रोग, स्त्री रोग, दंत रोग, नेत्र रोग सहित अन्य कई महत्वपूर्ण जाँच निःशुल्क की जावेगी एवं विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा । इस शिविर में विशेष रूप से मेमोग्राफी, सर्वाइकल, पेप स्मीयर, बायोप्सी, कॉल्पोस्कोपी, ईसीजी आदि जांचे प्रमुख रूप से की जाएगी । इस शिविर को लेकर मप्र जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष संजय नवलखा ने बताया कि शिविर के 200 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है । इस शिविर के साथ ही श्री आल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली की अल्पसंख्यांक योजना द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जैन समाज के लोगो को दी जा रही योजनाओं की जानकारी व उसका लाभ लेने की जानकारी के साथ जीवन प्रकाश योजना द्वारा प्रदत्त सुविधा की जानकारी भी दी जाएगी । इस शिविर मे जाँच कराना चाहती है वे अपना रजिस्ट्रेशन संजय नवलखा, मनोज मारू, सुमित चोरडिया के पास जल्द से जल्द करा लेवे, ताकि सिमित समय मे अधिक से अधिक परीक्षण करने का लक्ष्य में कोई परेशानी ना हो ।

मिशन एक लाख नौकरी की रफ्तार धीमी

नौकरी की रफ्तार विभागों की सुस्ती बनी चिंता का विषय

रंजीत टाइम्स

इंदौर 1 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साल में एक लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद जीएडी ने सभी विभागों को अपने यहां खाली पदों पर आवश्यकता के अनुसार भर्तियां निकालने का आदेश दिया है। इसके बाद कुछ विभागों ने तो अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं कुछ विभागों की सुस्ती चिंता बढ़ा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो शायद ही टारगेट पूरा हो सके। उच्च शिक्षा विभाग ने 2197 प्राध्यापक पदों के लिए जून और जुलाई माह में परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम तय कर लिया है। यह प्रक्रिया लंबे समय से खाली पड़े शिक्षण पदों को भरने की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है। वहीं, दूसरी ओर, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभागों में कुल 718 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हो सकी हैं। सूत्रों के अनुसार, लोक सेवा आयोग इन पर जल्द निर्णय ले सकता है, पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश के विभागों में एक लाख के करीब पद खाली पड़े हैं। कई विभागों में वर्षों से भर्तियां तक नहीं हुई हैं। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागों में भर्तियां शुरू हो रही है। गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है, लेकिन मुख्य परीक्षा, जो जून में प्रस्तावित थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में उन पदों पर भर्तियों की अंतिम घोषणा वर्ष के उत्तरार्ध तक खिंच सकती है। सरकारी आंकड़ों और दावों के बीच अंतर भी उजागर हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिसंबर 2024 में एक लाख पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां मंगवा कर पीएससी और चयन मंडल को भेजीं, लेकिन पीएससी, इंदौर ने अब तक केवल 64 विज्ञापन जारी किए हैं, जिनमें कुल 3151 पद शामिल हैं। इस अनुपात में रिक्त पदों की पूर्ति की रफ्तार धीमी मानी जा रही है। वहीं युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार किया था। कई युवाओं ने परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया और पढ़ाई में समय और धन निवेश किया। अब भर्ती प्रक्रिया के ठप हो जाने से उनमें निराशा और नाराजगी बढ़ रही है।

आरक्षण नियमों में उलझी 8,500 पुलिस पदों पर भर्ती

प्रदेश में 8,500 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया पिछले कई महीनों से आरक्षण नीति को लेकर अस्पष्टता और पीएचक्यू और कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच समन्वय की कमी के कारण अटकी हुई है। इन पदों में 7,500 आरक्षक (सिपाही) और 1,000 उपनिरीक्षक व लिपिकीय पद (स्टेनोग्राफर, सहायक आदि) शामिल हैं। यह भर्ती राज्य की कानून-व्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को भर्ती में आरक्षण की स्थिति को लेकर कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। साथ ही, उम्मीदवारों को राज्य सरकार के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इस नियम को लेकर भी विभागों के बीच मतभेद सामने आए हैं। यही कारण है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले मामला राज्य सरकार को भेजा गया है, ताकि वह इस पर अंतिम निर्णय ले सके।

अभ्यर्थियों का तारीख का इंतजार

प्रदेश में सबसे अधिक पद स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 579 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन अभी तक इनकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। इसमें सबसे अधिक 385 पद डेंटल सर्जनों के लिए हैं। इसके अलावा हड्डी रोग, नेत्र रोग, नाक-कान-गला, मानसिक रोग, फिजियोथेरेपी और क्षय रोग विशेषज्ञ जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों की जरूरत है। इससे साफ है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर विशेषज्ञों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन तारीख न तय होने से अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। कई विभागों में 194 पदों पर भर्ती प्रस्तावित, आयुष में 19 पदों के लिए होनी है परीक्षा वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा अन्य विभागों में भी भर्तियां प्रस्तावित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 120 पद सबसे अधिक हैं, इसके अलावा श्रम विभाग में 55 पद, पंचायत, जनसंपर्क, जल संसाधन, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग जैसे क्षेत्रों में भी भर्तियां की जानी हैं। इधर, आयुष विभाग में 19 पदों के लिए उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है। इसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं प्रदेश में पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वित्त अधिकारी, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत विकास और सहकारिता विभाग के पदों पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इनमें सबसे अधिक पद बाल विकास परियोजना अधिकारी (65) और महिला सशक्तिकरण अधिकारी (6) के लिए हैं। यह दर्शाता है कि महिला और बाल कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, शनिवार 24 मई 2025
03
DIGITAL EDITION

फूटा महिलाओं का आक्रोश, सालों से टूटी सड़क पर नहीं मिली सुनवाई तो पंचायत कार्यालय में फेंकी सरपंच-सचिव की कुर्सियां

उज्जैन। बड़नगर तहसील के ग्राम खरसोद कला में शुक्रवार को ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब वर्षों की उपेक्षा और टूटी सड़क की परेशानी ने उनकी सहनशक्ति की सीमा लांघ दी। नाराज महिलाओं ने सीधे पंचायत कार्यालय का रुख किया और सरपंच व सचिव की कुर्सियों को उठाकर बाहर फेंक दिया। इस विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गांव की मुख्य पड़निया रोड की हालत लंबे समय से बेहद खराब है। ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं का कहना है कि बीते ढाई सालों से लगातार पंचायत और जनप्रतिनिधियों को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल दिया गया। सड़क की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि बारिश के दिनों में वहां पैदल चलना तक असंभव हो जाता है। कीचड़, गड्ढे और फिसलन के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों, खेतों में काम करने वाले किसान और दैनिक जरूरतों के लिए बाहर जाने

वाली महिलाओं को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है।

महिलाओं ने आरोप लगाया कि पंचायत ने ना तो इस सड़क की मरम्मत कराई और ना ही किसी वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कराया। जब उन्होंने कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दीं, तो हर बार उन्हें सिर्फ "जल्द काम शुरू होगा" जैसा जवाब मिला। जब यह स्थिति जस की तस बनी रही और बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए, तब ग्रामीण महिलाओं ने प्रतिरोध का रास्ता चुना। उनका यह भी कहना है कि यह कोई राजनीति से प्रेरित कदम नहीं, बल्कि वास्तविक समस्या से उपजे जनाक्रोश का नतीजा है। गांव की महिलाओं ने पंचायत कार्यालय में पहुंचकर जब सरपंच और सचिव की कुर्सियां बाहर फेंकीं, तब वहां मौजूद अन्य ग्रामीणों ने भी इस विरोध को समर्थन दिया। उनका कहना है कि विकास के नाम पर केवल वादे होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यह विरोध प्रतीकात्मक जरूर था, लेकिन प्रशासन और शासन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि अब अगर जनसमस्याओं को हल्के में लिया गया, तो गांव-गांव में ऐसे दृश्य सामने आ सकते हैं। ग्रामवासियों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन नहीं लेंगे। यदि जल्द ही सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगली बार पंचायत के अधिकारी गांव में विकास कार्यों की बातें लेकर आएंगे, तो पहले उन्हें जवाब देना होगा कि पिछली समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ।

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर त्रिशूल से हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल, बुजुर्ग हमलावर गिरफ्तार

गुना। शनिवार को एक अजीब और चौंका देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिला दिया। मक्सूदनगढ़ ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस-प्रशासन की टीम पर एक बुजुर्ग ने अचानक त्रिशूल से हमला कर दिया। इस हमले में मक्सूदनगढ़ थाना प्रभारी सुरेश कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना उस समय हुई जब प्रशासनिक टीम बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जैसे ही पुलिस ने अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की, एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक आक्रोश में आ गया और उसने अपने पास रखा त्रिशूल निकालकर थाना प्रभारी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में टीआई को गंभीर चोटें आईं। आनन-फानन में अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन गहरी चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद बुजुर्ग आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह त्रिशूल को लहराते हुए नजर आ रहा है। वीडियो देखकर साफ है कि हमला सुनियोजित नहीं था, लेकिन उसकी तीव्रता बेहद खतरनाक थी, जिससे एक जिम्मेदार अधिकारी की जान खतरे में पड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। पुलिस ने हमलावर बुजुर्ग के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान किसी भी दबाव में रुकेगा नहीं और जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि मक्सूदनगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने हाल ही में विशेष मुहिम शुरू की है। लेकिन इस हमले ने यह भी उजागर कर दिया है कि कई जगहों पर प्रशासन को जनविरोध और अप्रत्याशित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। इससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या ऐसे अभियानों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है और क्या पुलिस बल को ऐसे संभावित खतरों के प्रति पहले से सतर्क किया जाता है।

PMT फर्जीवाड़ा मामला न्यायिक मोड़ पर खत्म: 'मुन्नाभाई' के आरोप में घिरे डॉक्टर और दलालों को CBI कोर्ट ने किया बरी, सबूतों की कमी बनी वजह

मध्यप्रदेश। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामला अब कानूनी रूप से लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गया है। ग्वालियर की सीबीआई विशेष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में आरोपी डॉक्टर और तीन कथित दलालों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इन चारों पर वर्ष 2009 में आयोजित पीएमटी परीक्षा में सॉल्वर के माध्यम से परीक्षा पास कराने का आरोप था। आरोपियों में डॉक्टर राहुल शर्मा, सोनू शर्मा, संतोष चौरसिया और धर्मेंद्र चंदेल शामिल थे, जिन्हें कई वर्षों तक इस केस में 'मुन्नाभाई' मॉडल के तौर पर पेश किया गया। मामले की शुरुआत एक गुमनाम शिकायत से हुई थी, जिसके आधार पर ग्वालियर के झांसी रोड थाना पुलिस ने डॉ राहुल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आरोप था कि राहुल शर्मा ने खुद परीक्षा नहीं दी, बल्कि किसी सॉल्वर को पैसे देकर अपनी जगह परीक्षा दिलवाई थी। यह मामला बाद में राज्य की विशेष जांच टीम (SIT) के पास गया और अंततः इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया।

CBI की जांच में राहुल शर्मा के अलावा दलाल बताए गए सोनू शर्मा, धर्मेंद्र चंदेल और संतोष चौरसिया के नाम सामने आए। एजेंसी ने दावा किया था कि राहुल ने पीएमटी पास करने के लिए सोनू शर्मा को चार लाख रुपये दिए थे, जिसने धर्मेंद्र चंदेल के जरिये यह काम आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र ने पूछताछ में बताया कि उसने संतोष चौरसिया की मदद से राहुल को परीक्षा पास कराई थी। जांच एजेंसी के अनुसार यह पूरा तंत्र छात्रों को पैसे लेकर परीक्षा पास कराने और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का काम करता था। हालांकि पूरे मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, यानी सॉल्वर की पहचान नहीं हो सकी। जांच एजेंसी यह साबित करने में विफल रही कि किस व्यक्ति ने राहुल शर्मा की जगह परीक्षा दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में दलालों द्वारा पैसे लेने की बात तो सामने आई, परंतु पैसे की बरामदगी नहीं हो सकी।

न्यायालय ने पाया कि इस मामले में आरोप तय करने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं हैं और सॉल्वर की अनुपस्थिति केस को संदेह के घेरे में डालती है। सीबीआई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर अवश्य थे, परंतु केवल कथनों या आंशिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि आपराधिक मामलों में अभियोजन को आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस और संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं, जो कि इस केस में नहीं हो सका। चारों आरोपियों की वर्षों की कानूनी लड़ाई, मीडिया में बदनामी और सामाजिक अपमान के बाद अब उन्हें राहत तो मिली है, लेकिन यह मामला एक बार फिर उस बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है, जहां व्यवस्थाएं तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गठित की जाती हैं, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही वे खुद प्रक्रिया में उलझ जाती हैं। यह फैसला न केवल जांच एजेंसियों के लिए आत्मविश्लेषण का विषय है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि जब आरोप गंभीर हों और समाज पर प्रभाव डालते हों, तब साक्ष्य की कमजोरी क्यों सामने आती है? क्या यह केवल जांच की तकनीकी कमियों का परिणाम है, या फिर सिस्टम के भीतर फैली गहराई तक की लापरवाही का नमूना?

लव जिहादी मोहसिन तेरी करतूतों का भंडाफोड़ हो गया...
तेरे दिमाग को कट्टरता का कोड हो गया..

प्रो(डॉ.) श्याम सुन्दर पलोड
लेखक , कवि एवं वक्ता
स्वरदूत - 9893307800

प्रखर वाणी

वाह रे दरिंदे मोहसिन खान...हिन्दू लड़कियों से छेड़छाड़ को मानता था शान...लव जिहादी तेरी करतूतों का भंडाफोड़ हो गया है...तेरे दिमाग को कट्टरता व धर्म का कोड हो गया है...तू निशानेबाजी का कोच बनकर कहीं और निशानेबाजी करता रहा...तेरी गन्दी हरकतों का कारनामा कई लड़कियों को अखरता रहा...क्या तेरी हिम्मत थी तूने हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया...रक्षासूत्र खुलवा दिए गोमांस खिलवा दिया कुरान पढ़ने की विवशता का पैगाम दिया...तेरे नफरती कांड के पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है...सच सच बता ऐसे कितने जुनूनी तेरे साथ हैं...क्या ऐसे घिनौने प्रपंच की भी तालीम तुझे कहीं मिली है...शूटिंग की आड़ में अपनी ही शिक्षार्थियों को बेड टच करके तेरी आत्मा खिली है...हुस्न की हवस में शैतानियत की रूह को लव जिहाद से जोड़ने वालों...भारत की एकता व अखण्डता को धूमिल करने वाले मकड़ी के जालों...तुम्हारी सोच को कुकृत्य के मानिंद गन्दा करके अपराध करते हो...ऐसी घटनाएं और बार बार घृणित घटनाक्रम संग निर्बाध करते हो...तुमको तो कई मुस्लिम राष्ट्रों की सार्वजनिक सजा की भांति चौराहे पर बांधकर पत्थरों से पीटना चाहिए...तुम्हारे शरीर की बोटी बोटी नोंचकर जोरदार ढंग से घसीटना चाहिए... अपनी शैतानियत की सल्तनत के दुष्ट हुक्मरानों... तुम्हारी अब उलटी गिनती शुरू हो गई है मोदी - योगी युग में ये मानो...मोहन की मुरली ही देखी है अब सुदर्शन चक्र चलेगा ये जान लो...बर्दाश्त करने योग्य नहीं है तुम्हारा कृत्य ये तुम तुम्हारे आकाओ सहित मान लो...अब नगाडा बज चुका है लव जिहाद के विरुद्ध युद्ध का...जन आक्रोश भी फूट गया है तुम्हारे खिलाफ एक एक क्रुद्ध का...अब और शोषण और दुष्कर्म बर्दाश्त नहीं होगा...तुम्हारी साजिशों को सीमा के भीतर व बाहर भोगा... जाल फैलाकर मछलियां पकड़ते तो फिर उनकी तड़पन पर आनन्द उठाते हो... बहरूपिया बनकर दोस्ती करते हो फिर अपना असली चेहरा दिखाते हो...तुम्हारी वहशियाना अदाओं पर अब चाबुक चलेगा...हर एक शिकंजे में होगा जो लव जिहाद में छलेगा....

सिघई ललित जैन को आगर संभाग का जैन पत्रकार संपादक संघ का समन्वयक (संयोजक) बनाया गया

रंजीत टाइम्स

सुसनेर सुसनेर I मध्य प्रदेश जैन पत्रकार संपादक संघ का आगर जिले का समन्वयक नियुक्त किया गया

सुसनेर धर्म प्राण नगरी सुसनेर के देव शास्त्र गुरु के परम भक्त व्यवहार कुशल प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी जैन समाज के गौरव श्री जैन सहयोग ग्रुप के संरक्षक पार्श्वनाथ चेरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक नगर के प्रतिष्ठित बड़ा जीन वाला परिवार के श्री शांति बाई फूलचंद जी जैन के अंतिम पुत्र सिघई ललित जी जैन को आगर मालवा जिला का समन्वयक (संयोजक) मनोनीत किया गया। आप कई वर्षो से जैन धर्म की सेवा कर रहे है आपका पूरा परिवार धर्मनिष्ठ व्यवहार कुशल प्राभवशाली है। आपके माता पिता ने आपने सद संस्कारो का बीजारोपण कर दिया था इनके सामाजिक सेवाओं की भावना अनुरूप इन्हें आगर मालवा जिला के समन्वयक मनोनीत किया गया I इनके मनोनयन पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पारस जैन पार्श्वमणि पत्रकार कोटा राजस्थान ने हार्दिक शुभकामनाए समर्पित की

बार-बार क्यों टल रहे हैं...सहकारी समितियों के चुनाव इसी माह से शुरू होनी थी प्रक्रिया

रंजीत टाइम्स

भोपाल I सहकारी समितियों के चुनाव मप्र में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव पिछले 12 वर्षों से लंबित हैं। अब एक बार फिर इन चुनावों को टाल दिया गया है। सरकार ने समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का हवाला देकर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। सहकारिता विभाग की योजना अनुसार, हर पंचायत में एक नई साख सहकारी समिति गठित की जानी है। राज्य में परीक्षण के बाद करीब 650 नई समितियां बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 189 समितियों का गठन ही पूरा हुआ है। प्रदेश की 4,500 से अधिक सहकारी समितियों के चुनाव अंतिम बार 2013 में कटाए गए थे, जिनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया। नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पूर्व शुरु हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक कारणों, विधानसभा चुनाव, और किसान कर्जमाफी जैसी वजहों से चुनाव बार-बार टलते रहे। इस मुद्दे पर जबलपुर और ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठों में याचिकाएं दाखिल हुई, जिसके बाद राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने मई से सितंबर 2025 के बीच चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था। लेकिन अब सरकार फिर से अदालत पहुंची और नई समितियों के गठन की अधूरी प्रक्रिया का हवाला देते हुए चुनाव टालने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

नई समितियों के गठन का हवाला दरअसल, सहकारिता मंत्रालय ने प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक साख सहकारी समिति गठित करने के लिए कहा है। प्रदेश में परीक्षण करने के बाद लगभग साढ़े छह सौ समितियां बनाने का निर्णय हुआ है। इनमें से अभी मात्र 189 समितियां गठित करने की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसे देखते हुए चुनाव टाल दिए गए। उधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार समितियों की कमान किसानों के हाथों में सौंपना ही नहीं चाहती है, इसलिए किसी न किसी बहाने से बार-बार चुनाव टाले जा रहे हैं। प्रदेश की साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव आखिरी बार 2013 में हुए थे, जिनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हुआ। नियमानुसार छह माह पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा चुनाव, किसान कर्ज माफी और अन्य कारणों से चुनाव प्रक्रिया लगातार टलती रही। चुनाव नहीं होने के कारण हाई कोर्ट की जबलपुर व ग्वालियर खंडपीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं।

घोषित हुआ था चुनाव कार्यक्रम महाधिवक्ता कार्यालय के सुझाव पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने मई से सितंबर 2025 के बीच चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। यह प्रक्रिया प्रारंभ हो पाती इसके पहले सरकार फिर हाई कोर्ट पहुंच गई और चुनाव आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी। इसका आधार सहकारिता मंत्रालय के नई समितियों के गठन के दिशानिर्देश पर प्रचलित प्रक्रिया को बनाया। हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और एक बार फिर चुनाव टल गए। जबकि, चार चरण में प्रस्तावित कार्यक्रम में यह व्यवस्था रखी गई थी कि पहले चरण में उन समितियों को ही शामिल किया जाएगा, जो पुनर्गठित हो चुकी हैं। फिर जैसे-जैसे पुनर्गठन की प्रक्रिया होती जाएगी, वैसे-वैसे पुनर्गठित समितियों को शामिल किया जाता रहेगा।

दिग्विजय ने सीएम को लिखा पत्र

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सहकारिता के चुनाव न कराने पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत 12 सालों से चुनाव ही नहीं कराए गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव न कराने पर राज्य सरकार पर पेनाल्टी लगाने के बाद भी चुनावी प्रक्रिया अभी तक शुरू नही की गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से लेकर जिला और शीर्ष संस्था अपेक्स बैंक तक सरकारी तंत्र के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने मांग की कि सभी समितियों के चुनाव तीन माह के भीतर कराए जाएं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था से निर्णय हों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सहकारी समितियों की कमान आ सके। सहकारिता चुनावों को बार-बार टालना न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभ किसानों को निर्णय की शक्ति से दूर रखने का संकेत भी है। अब देखना होगा कि सरकार अगले तीन महीनों में इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है या यह सिलसिला जारी रहता है।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, सोमवार 26 मई 2025

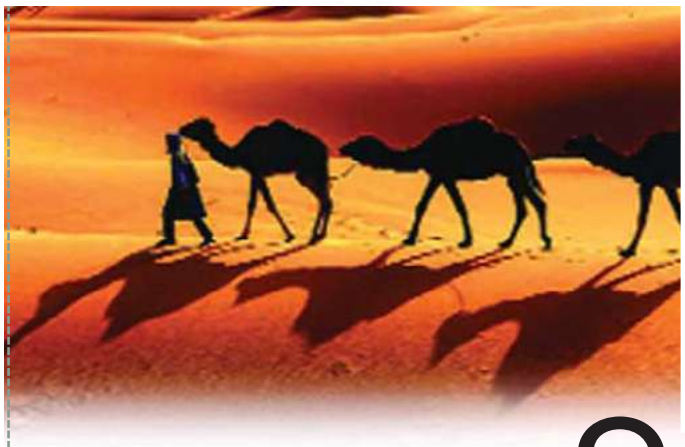

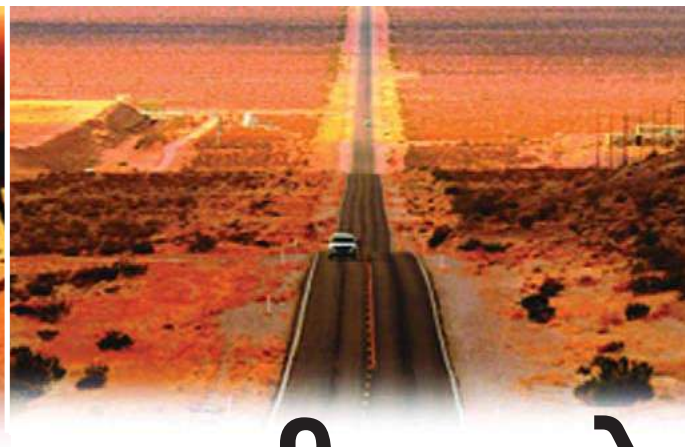

दुनिया की सबसे गर्म जगहें

भारत समेत दुनिया के कई देश इन दिनों गर्मी का सामना कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी कड़ी में आज हम आपको दुनिया की पांच ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि लोगों की जान भी जा सकती है। यह जगहें इतनी गर्म होती हैं कि यहां पर 10 मिनट में इंसान बीमार पड़ सकता है या कुछ घंटे में ही उसकी मौत हो सकती है।

सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका

दुनिया की सबसे गर्म जगहों में अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान भी शामिल है। इस जगह का औसत तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पूरे साल यहां 100 मिलिमीटर से भी कम बारिश होती है, जो न के बराबर है। सहारा रेगिस्तान में अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्यिस रिकॉर्ड किया गया है। सहरा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है।

डेथ वैली, कैलिफोर्निया

कैलिफोर्निया की डेथ वैली दुनिया की सबसे अधिक गर्म जगहों में से एक है। 10 जुलाई 1913 में यहां पर अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड बना था। उस समय डेथ वैली के फरनेस क्रीक नामक स्थान पर अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। फिलहाल यहां पर 37 से 40 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जाता है। यहां पर गर्मी की कई वजहें हैं जिनमें सूरज की गर्मी, घाटी में गर्म हवाओं का बाहर नहीं जा पाना और फंसकर घूमता रहना है। इसके साथ ही आसपास रेगिस्तान मौजूद हैं, जहां से गर्म हवाएं आती हैं। यहां के जलीय स्रोतों से ह्यूमिडिटी निकलती है, जिनकी वजहों से डेथ वैली में जानलेवा गर्मी पड़ती है।

फ्लेमिंग माउंटेन, चीन

चीन का फ्लेमिंग माउंटेन टकलामाकेन रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में स्थित है। शिनजियांग प्रांत के तियान शान में स्थित लाल सैंडस्टोन्स की पहाड़ियों को फ्लेमिंग माउंटेंस या हुओयान माउंटेंस भी कहा जाता है। इस पहाड़ की लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर है। इस जगह गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बताया जाता है कि साल 2008 में इस इलाके में 66.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड पहुंच था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

ल अजीजिया, लीबिया

लीबिया के उत्तर-पश्चिम इलाके में स्थित जाफरा जिले में अजीजिया एक छोटा सा कस्बा है। इस इलाके में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। आमतौर पर यहां का उच्चतम तापमान 35 से 40 के बीच रहता है, लेकिन 13 सितंबर 1922 में 58 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन बाद में विश्व मौसम संगठन ने साल 2012 में इसको गलत बताया था, क्योंकि उस समय तापमान मापने की सुविधा इस इलाके में नहीं थी। हालांकि इस इलाके में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है।

सोनोरन रेगिस्तान, अमेरिका

अमेरिका से उत्तरी मेक्सिको तक यह रेगिस्तान फैला है, जहां पर जानलेवा गर्मी पड़ती है। इसके साथ ही यहां कैक्टस के पौधे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। यह रेगिस्तान एरिजोना प्रांत में स्थित है जहां कुछ दुर्लभ जगुआर देखने मिलते हैं। यहां का औसत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है।

60 हजार साल पुरानी बांसुरी है स्लोवेनिया के म्यूजियम में ...

निएंडरथल मानव भी संगीत प्रेमी रहा होगा इसका सबूत है यह हजारों साल पुरानी बांसुरी। चित्र में दिखाई दे रही बांसुरी दुनिया की सबसे पुरानी बांसुरी बताई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार करीब 60 हजार साल पुरानी है ये बांसुरी। इसकी पड़ताल करने के बाद विशेषज्ञों ने पाया है कि इसे निएंडरथल मानव ने युवा भालू की जांघ की हड्डी से उस काल में बनाया था। इस बांसुरी को स्लोवेनिया के तटीय क्षेत्र के एक छोटे से शहर सेर्कनो की प्राचीन गुफाओं में खोजा गया है और इसमें आजकल की सामान्य बांसुरी की तरह छेद भी हैं। इसमें कुल 4 छेद हैं। विशेषज्ञों ने बारीकी से जांच करने के बाद जो जानकारियां जुटाई हैं, उनमें उन्हें पता चला है कि इसके छिद्रों और इनका आकार-प्रकार पूरी तरह से एक साज को दिमाग में रखकर उस समय के मानव ने बनाया है। मतलब वे संगीत प्रेमी भी थे और निर्माण कौशल भी उनमें था। वर्तमान में 11.4 सेमी की इस बांसुरी के इस अवशेष को स्लोवेनिया के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है।

लोग मिलते रहे, इसलिए हैलो किटी की थीम पर बनाया कैफे

कनाहा के बैंकूवर में मशहूर कार्टून हैलो किटी की थीम पर एक कैफे बना हुआ है। यह कैफे दोपहर में खुलता है। लेकिन हैनो किटी के प्रशंसकों की लाइन्स सुबह से ही इस कैफे के बाहर लग जाती हैं। कैफे के मालिक केन लेम चेठक हैंग का कहना है कि कोविह महामारी के बाद लोगों ने मिलना-जुलना काफी हद तक बंद कर दिया था। हम कुछ ऐसा करना चाहता थे कि लोग मिल सके, बैठ सके और बातचीत कर सकें। इसलिए लैम ने हैलो किटी कैफे खोलने का विचार किया। यहां मिलने वाली चाय और केक हैलो किटी की थीम पर आधारित हैं। इसके अलावा आप यहां से हेलो किटी की थीम पर आधारित बेसबॉल और मग भी खरीद सकते हैं।

आराम के लिए बनाए बूथ

कैफे में सबसे ज्यादा आइस्ड मिल्क टी पी जाती है। इसमें चमेली का हल्का स्वाद होता है। कैफे में मशहूर पॉप कल्बर आइकन के इर्द-गिर्द रंग और सजावट की गई है। कैफे की दूसरी मंजिल पर हैलो किटी का सिग्नेचर धनुष रखा हुआ है। यहां खाने के लिए सुंदर बुध बनाए गए हैं, जहां आप आराम भी कर सकते हैं। कैफे के मालिक लेम का कहना है कि हेलो किटी 50 सालों से दोस्ती और दयालुता की राजदूत ही है और यह कैफे उनका जश्न मनाने की शानदार जगह है।

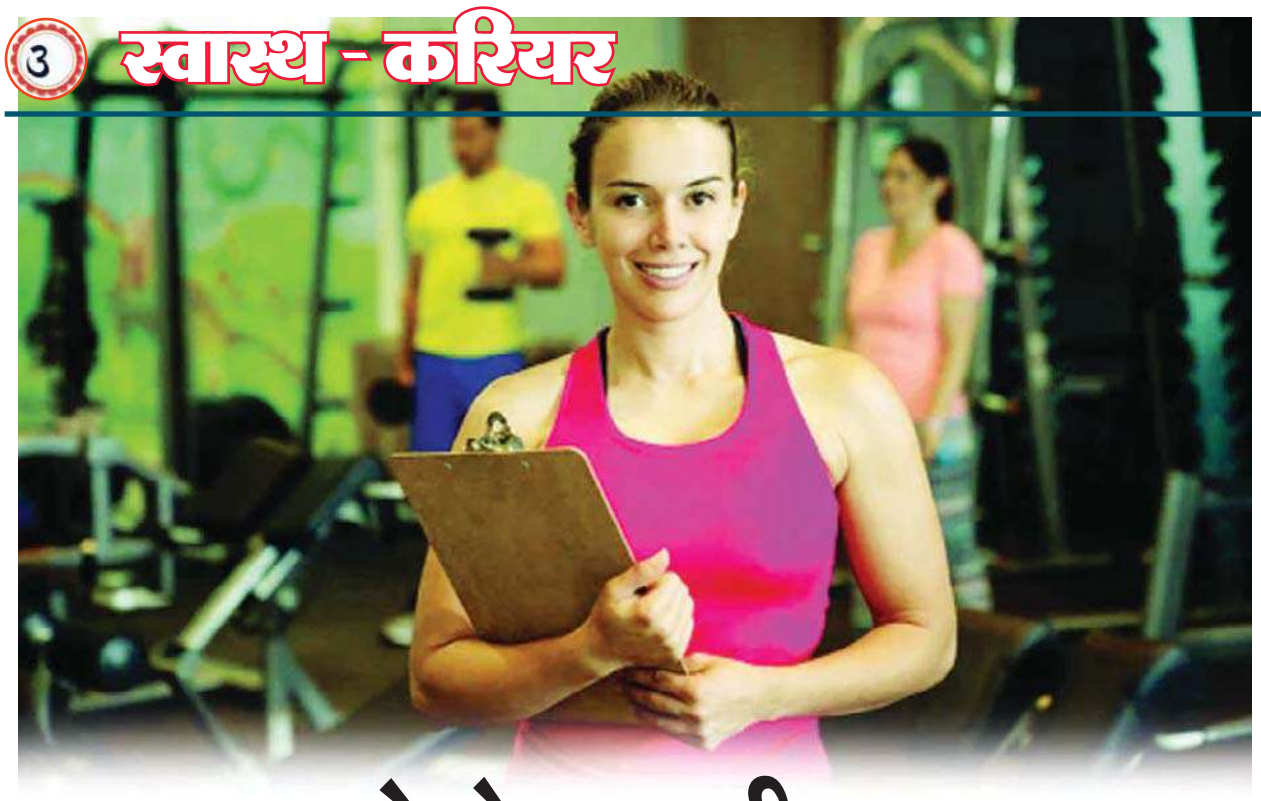

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी जागरूकता के कारण जिम व्यवसाय में बहुत है स्कोप

स्वास्थ्य को लेकर लोगों के बीच में बढ़ी जागरूकता के कारण इस व्यवसाय में आपके लिए बहुत स्कोप है। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा।

आज की नई पीढ़ी अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरुक है और यही वजह है कि उनका रुझान जिम की ओर बढ़ता जा रहा है। अपने फिटनेस के लिए लोग हर महीने हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, ऐसे में आए दिन जिम की मांग बढ़ती जा रही है। जिम के बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार निवेश करने के बाद कई सालों तक इससे अच्छी कमाई हो सकती है। लोग इन दिनों छोटी-छोटी जगहों पर जिम खोलकर पैसे कमा रहे हैं और अगर आपको भी फिटनेस का क्रेज है और आप भी जिम खोलना चाहती हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं जिम का बिजनेस कैसे शुरु कर सकती हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको बता दें कि जिम दो तरह के होते हैं पहला जिसमें वेट लिफ्टिंग और कार्डियो उपकरणों आदि की सुविधा होती है। इसमें बॉडी बनाने, वजन कम करने इत्यादी की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा है फिटनेस सेंटर, इसमें योगा, एरोबिक्स, वजन घटाना, वजन बढ़ाना, मार्शल आर्ट, आसन इत्यादि सिखाएं जाते हैं, फिटनेस सेंटर का बिजनेस जिम की तुलना में थोड़ा महंगा होता है।

प्रशिक्षित होना जरूरी

अगर आप जिम खोलना चाहती हैं तो आपका प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आप स्वयं प्रशिक्षित नहीं हैं तो आप अपने जिम में ट्रेनर या कोच रख सकती हैं लेकिन ट्रेनर या कोच के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को ही प्राथमिकता दें।

जिम का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं

आपको बता दें कि जिम का रजिस्ट्रेशन स्माल स्केल इंडस्ट्री के तहत होता है, इसके लिए जिले के उद्योग विभाग से फॉर्म लेना होगा। इस फॉर्म को भरकर जमा करने पर आपको जिम खोलने का लाइसेंस मिल जाता है। शुरुआत में आपको उद्योग विभाग अस्थायी लाइसेंस देगा, बाद में आप स्थायी लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। आजकल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था है।

जगह का चयन

फिटनेस सेंटर या जिम खोलने के लिए जगह का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसे किसी प्राइम लोकेशन पर ही खोलें, आप चाहे तो इसे किसी छोटी सी जगह पर भी खोल सकती हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि जहां भी आप जिमखोल रही हैं वहां आने वालों के लिए पार्किंग की सुविधा जरुर हो। जिम खोलने के लिए आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट लेना होगा लेकिन आपका बजट अगर कम हो तो आप इसे कम जगह में भी खोल सकती हैं। वहीं, आप जिम किसी भी फ्लोर पर शुरु कर सकती हैं।

मशीनों की जरूरत

एक सामान्य जिम खोलने के लिए आपको कम से कम पद्रंह तरह की मशीनों की जरुरत पड़ेगी। जिन मशीनों की जरुरत होती है, उनमें बेंच प्रेस, ट्रेड मिल, लेग प्रेस, बटर फ्लाई, लैट पुल डाउन, पैक डेक, डिप बार, केबल क्रॉस ओवर, प्रीचर बेंच, सिटअप बेंच, दो नॉर्मल बेंच, स्किपिंग रोप, योगा मैट, रॉड, डंबल, स्टैंड इत्यादि। इन मशीनों में सबसे महंगा ट्रेड मिल है इसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये है। इसके अलावा आपको लाइट, म्यूजिक सिस्टम, एसी और इंटीरियर डेकोरेशन के कुछ सामान खरीदने होंगे।

जिम का प्रचार कैसे करें

जिम की आमदनी वहां आने वाले ग्राहकों पर ही निर्भर करती है और इसके लिए आपको जिम का प्रचार-प्रसार करना होगा और जिम की जानकारी देनी होगी। इसके लिए आप उस इलाके के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगवा सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रचार करवा सकती हैं। लोकल न्यूज चैनल और अखबारों के माध्यम से प्रचार कर सकती हैं।

जिम में महीने का खर्च

जिम खोलनेपर आपको महीने में कम से कम 70,000 रूपये खर्च करने होंगे। इसमें मकान का किराया, बिजली बिल, मशीनों पर खर्च, ट्रेनर और अन्य कर्मचारियों का वेतन इत्यादि शामिल होंगे। अगर आप खुद ट्रेनर हैं तो अपने कुछ पैसे बचा सकती हैं।

आमदनी और फीस की जानकारी

आमतौर पर जिम की फीस दस हजार रुपये मासिक होती है। इस हिसाब से अगर आपके जिम में कम से कम दो सौ लोग भी नियमित रूप से आते हैं तो आपको फीस से दो लाख रुपये की आमदनी होगी। वहीं, अगर छोटे-मोटे खर्चों को निकाल दे तो आपको हर महीने कम से कम एक लाख रुपये की आमदनी होगी। खरीदी गई मशीनों का कॉस्ट निकल जाने के बाद आपकी कमाई बढ़ जाएगी।

इन बातों का रखें ध्यान

जिम के लिए आने वाले व्यक्ति से मान्यता प्राप्त डॉक्टर या अस्पताल का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर मांगे। अगर किसी भी कस्टमर को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी तो वह आप पर क्लेम नहीं कर पाएगा। आप अगर जिम के साथ-साथ सप्लीमेंट का भी बिजनेस कर रही हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचें, नहीं तो आपकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

करियर स्विच करने से पहले जरूर सोचें

क्या आपको अपने काम से संतुष्टि नहीं मिलती? क्या आप हर दिन ऑफिस जबरदस्ती जाती है? ऑफिस जाने के बाद आपकी नजर सिर्फ घड़ी पर होती है? अब आपको अपने काम में बोरियत महसूस होती है और आप अपने करियर को स्विच करने के बारे में सोच रही है? अगर इन सभी सवालों के जवाब हां हैं तो इसका अर्थ है कि आपको शांति से बैठकर खुद से कुछ सवाल करने की जरूरत है।

दरअसल, हर दिन एक ही काम करते-करते बोरियत होने लगती है और फिर आपका मन उस काम में नहीं लगता। ऐसे में आप कुछ नया करने के बारे में सोचती हैं, लेकिन करियर स्विच करने का फैसला इतना भी छोटा नहीं है। करियर स्विच करने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम आपको उन बातों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में आपको करियर स्विच करने से पहले जरूर सोचना चाहिए-

बरतें ईमानदारी

करियर स्विच करना जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला है और इसलिए इस फैसले को लेने से पहले आपको खुद के साथ ईमानदारी बरतना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आप खुद से यह सवाल पूछें कि क्या सच में आप अपना करियर स्विच करना चाहती हैं और क्या आप जो रही हैं, उसमें आपका पैशन नहीं है। दरअसल, जिस काम को करना आप पसंद नहीं करती, उससे बेहद जल्द बोर हो जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है और हर दिन एक ही काम करने के कारण आपके भीतर यह उबाउपन है तो करियर स्विच करने की बजाय कुछ नई जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करें।

शुरूआत से शुरू

जब आप किसी नई फील्ड में खुद को स्थापित करने की कोशिश करती हैं तो इसमें एक लम्बा वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप करियर स्विच करने की सोच रही हैं तो अगले दिन ही आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या आप सफलता की उस बुलंदी पर पहुंच जाएंगी, जिसकी आपको इच्छा है। तो खुद से यह जरूर पूछें कि क्या आप दोबारा उतनी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं?

फाइनेंशियल प्रभाव

जब आप अपना करियर स्विच करती हैं तो इसका आपके जीवन पर फाइनेंशियली भी काफी असर पड़ता है। हो सकता है कि इस जॉब में आप एक अच्छी पोस्ट पर हाई सैलरी में हों। लेकिन जब आप करियर स्विच करेंगी तो आपको बेसिक सैलरी से ही काम की शुरूआत करनी होगी। क्या आप सैलरी में इस गिरावट को मैनेज कर सकती हैं और इससे आपके मासिक खर्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमूमन देखने में आता है कि कुछ लोग अपने काम से परेशान होकर जॉब तो स्विच कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें सैलरी मनमुताबिक नहीं मिलती तो उन्हें पहले की जॉब व काम ही अच्छा लगता है और करियर चेंज का फैसला उन्हें गलत नजर आता है।

पारिवारिक प्रभाव

आपका करियर चेंज का फैसला सिर्फ आपको ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इससे आपका पूरा परिवार जुड़ा होता है। दरअसल, हर जॉब की अपनी मांग व जरूरतें होती हैं। कुछ काम को करते समय आपको काफी घूमना पड़ता है तो किसी काम में आपको लेट नाइट काम करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी फैमिली पर उसका असर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी फील्ड में जाने से पहले यह भी अवश्य देखें कि इससे आपके परिवार व पारिवारिक जिम्मेदारियों पर कितना असर पड़ रहा है और क्या आप और आपका परिवार इस बदलाव के लिए तैयार है।

लें प्रोफेशनल हेल्प

अगर आप खुद को असमंजस की स्थिति में पाती हैं और किसी भी निर्णय को लेने में असमर्थ हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी करियर काउंसलर की मदद लें। आप उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं और साथ ही यह भी बताएं कि आप अपना करियर चेंज क्यों करना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त आप किस फील्ड में जाने का मन बना रही हैं। इस तरह आपकी पूरी स्थिति को जानने के बाद एक करियर काउंसलर आपको सबसे बेस्ट सलाह देगा। साथ ही आपकी रूचि के अनुसार कुछ ऐसे ऑप्शन भी बताएगा जो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इसलिए करियर चेंज करने से पहले एक बार करियर काउंसलर से मिल लेना काफी अच्छा रहेगा।

कुछ इस तरह सेट करें मंथली बजट

हर व्यक्ति अपनी पसंद व स्किल्स के अनुसार ही काम का चयन करता है और इसलिए हर किसी का काम व इनकम अलग होती है। जहां कुछ लोग 9 से 5 की जॉब करते हैं और उनकी फिक्स सैलरी होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी जॉब में नहीं होती। बल्कि उनका काम कुछ ऐसा होता है कि उनकी इनकम ऊपर-नीचे होती रहती है। मसलन, अगर आपका अपना कोई काम है, तो आप महीने में होने वाली आमदनी को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसी तरह, अगर आप बतौर फ्रीलासंर फुल टाइम वर्क करते हैं, तो आपकी आमदनी आपको मिलने वाले प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करेगी।

इस तरह के कामों में आमदनी कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत ही कम होती है। इस तरह सैलरी फिक्स ना होने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपके लिए घर का खर्च उठाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। चूंकि, आपकी आमदनी फिक्स नहीं है तो उसके अनुसार आप अपनी सैलरी को सही तरह से मैनेज नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा है, तो ऐसे में आप अपना मंथली बजट सेट करने के लिए इन आसान टिप्स की मदद लें

अनुमानित आय का करे आकलन

यह सच है कि आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को मिलने वाले काम के अनुसार अपनी आय का एक अनुमान तो लगा ही सकती हैं। अगर आपकी आय ऊपर-नीचे होती भी होगी, तो उसमें पांच-दस हजार का अंतर आता होगा। इसलिए, आप पिछले एक वर्ष की आय का अंदाजा लगाते हुए यह जानने का प्रयास करें कि आपकी महीने में लगभग कितनी इनकम होती है। जब आप अपनी आय का आकलन करेंगी, तभी आप बजट सेट कर सकती हैं।

जरूरी खर्चों की बनाएं लिस्ट

अब वक्त है जरूरी खर्चों की लिस्ट तैयार करने का। मसलन, बच्चों की फीस से लेकर ईएमआई, घर का किराया व बिजली बिल आदि जरूरी खर्चों की एक लिस्ट तैयार करें। इससे आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि वास्तव में कितने खर्चे ऐसे हैं, जो आपको हर महीने करने ही होंगे और उसके अनुसार आपकी इनकम कितनी है।

निकालें सेविंग्स का एक हिस्सा

जब आप जरूरी खर्चों व इनकम के बीच के अंतर के बारे में जान जाते हैं, तो आपको बची हुई इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स के लिए निकालना होगा। आपके द्वारा की गई सेविंग्स आपकी इनकम के आधार पर कम

या ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप सेविंग की आदत को कभी भी ना छोड़ें। चूंकि आपकी इनकम कभी भी एक जैसी नहीं रहती है और इसलिए आपके लिए सेविंग्स करना बेहद आवश्यक हो जाता है।

बनाएं इमरजेंसी मनी बैंक

यह इमरजेंसी मनी बैंक उस वक्त के लिए बनाना आपके लिए आवश्यक है, जब आपकी इनकम बहुत कम हो जाती है और आपके लिए अपनी आय से जरूरी खर्चों को कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त यह इमरजेंसी मनी बैंक काम आता है। अगर इस वक्त आपका काम अच्छा चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बेफिजूल खर्चों में पैसों को बर्बाद कर दें। आपको अपना मंथली बजट यूं सेट करना चाहिए कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंटरटेनमेंट के लिए तो एक हिस्सा इमरजेंसी मनी बैंक के लिए रखें। यह छोटा सा मनी बैंक आप खुद घर में ही बना सकते हैं या फिर ऐसे किसी स्कीम में इनवेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पैसे धीरे-धीरे कुछ हद तक बढ़ते रहे और जब भी आपको उसकी जरूरत हो, आप उसे निकाल सकें।

ऐप की लें मदद

यह मंथली बजट बनाने का सबसे आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। आजकल ऐसे कई ऐप हैं, जिन्हें आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद, आप उसमें हर माह की आय लिख सकती हैं और मंथली बजट लिमिट एड कर सकती हैं। उसके बाद आप हर दिन होने वाले खर्चों को उसमें एड करती जाएं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आप सबसे अधिक खर्चा कहां कर रही हैं और क्या आप अपने मंथली बजट के अनुसार खर्चे कर रही हैं। इस तरह आपके लिए बजट में रहना आसान होगा और अपनी आय व खर्चों को ट्रैक करने में भी आपको मदद मिलेगी।

घर-परिवार की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए बचत बहुत जरूरी

महिलाएं चाहती हैं कि घर परिवार में संपन्नता रहे, परिवार के सदस्यों को रुपये-पैसे की कमी ना आए, इसके लिए महिलाएं अपनी खर्चों में भी काफी कटौती करती हैं। इसके बावजूद अक्सर ऐसा होता है कि महीने के आखिर तक आते-आते पैसे खत्म हो जाते हैं और सेविंग्स भी नहीं हो पातीं। घर-परिवार की इमरजेंसी की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए महिलाओं के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्च बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से आपकी सेविंग्स नहीं हो पातीं, तो आपको नए नजरिए से सोचने की जरूरत है। आपकी आमदनी चाहें भले ही कम क्यों ना हो, अगर आप घर का बजट सही तरीके से बनाएं, तो आप थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करके भी बड़ी बचत कर सकती हैं। आइए जानते हैं महीने का बजट बनाने के कुछ ऐसे तरीके, जिनसे आपका घर का फाइनेंस अच्छे तरीके से मैनेज होगा, जरूरी खर्चों के लिए पैसे रहेंगे और आप सेविंग्स करने में भी कामयाब होगीं।

- बजट बनाने में सबसे पहले अपने बड़े और जरूरी खर्चों की लिस्ट बना लें, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का राशन, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बकाया आदि।
- बजट बनाने में खाने-पीने की चीजों पर कटौती नहीं करें। अगर आप अनाज जैसे कि दाल, गेंहू, चावल, मसाले आदि थोक की दुकान से खरीदेंगी तो पैसे की बचत के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी का सामान भी खरीद सकती हैं। मुमकिन हो तो सुपर मार्केट के बजाय लोकल मार्केट से ही अच्छा सामान खोजने की कोशिश करें। साथ ही मॉल में छोड़े-बड़े सामान पर मिलने वाले ऑफर और सेल का भी आप फायदा उठा सकती हैं।
- घर का बजट बनाते हुए उसमें अपने, अपने परिवार के बड़ों और बच्चों के खर्च जरूर शामिल करें। आप चाहें तो उनसे इस बारे में एक बार बात भी करें और उसी के आधार पर सबके लिए बजट निर्धारित कर लें।
- बिजली और गैस का यूज जरूरत के हिसाब से करें। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी-छोटी बचत भी आपके लिए अच्छी सेविंग्स का साधन बन सकती हैं, बजट को और मजबूत बना सकती हैं।
- बजट बनाते समय अपनी इनकम और खर्चे का रिकार्ड साथ में रखें, क्योंकि इसी के आधार पर आप सेविंग्स के लिए अपना टार्गेट सेट कर सकती हैं और एक अच्छा बजट बना सकती हैं। इसके लिये एक निर्धारित फॉर्मेट बना लें और उस पर अपनी इनकम और होने वाले खर्चों को उसमें जोड़ते जाएं।
- अपनी पसंद वाली छोटी और बड़ी चीजों की एक लिस्ट अलग से बनायें, जिन चीजों की जरूरत ज्यादा है, उन्हें प्रायोरिटी पर रखें। कभी-कभी मजे-मजे में अनावश्यक फिजूलखर्ची भी हो जाती है और इससे बाद में परेशानी होती है। इसे देखते हुए जब भी पार्टी करने जाएं या आउटिंग पर जाएं तो उसके लिए अपने खर्च की लिमिट पहले से ही सोच लें।
- बजट को बोझ समझकर मन छोटा ना करें। शुरूआत में आपको इससे प्रेशर फील हो सकती है, लेकिन इससे होने वाली बचत से आपको बाद में बड़े फायदे हो सकते हैं।
- बजट बनाने से आप अपने खर्चों पर असरदार तरीके से काबू रख सकती हैं और फाइनेंशियली मजबूत हो सकती हैं।
- बजट बनाते हुए अलग-अलग खर्चों के लिए अलग लिफाफे रखें, ताकि फाइनेंस के मामले में आप पूरी तरह से ऑर्गनाइज रहें। इससे आपको महीनेभर खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इमरजेंसी की जरूरतों के लिए एक लिफाफा अलग से बनाएं और इसमें भी कुछ रुपये अलग से रखें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और इससे आपका महीने का बजट पूरी तरह से बिगड़ सकती है।

सेवाभाव की राजनीति में उतरी कांग्रेस, आरएसएस के मुकाबले सेवादल को बना रही आधार, राहुल गांधी के पायलट प्रोजेक्ट से गरमाई सियासत

भोपाल। सेवाभाव की राजनीति को लेकर। केंद्र में है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले विदिशा जिले से हो रही है। कांग्रेस इस प्रयोग के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संगठित ढांचे और सामाजिक प्रभाव के समांतर एक सेवा-आधारित नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है।

जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रयास को पूरी तरह से 'नकली और असफल प्रयोग' बताया है, जबकि कांग्रेस इसे अपने "सेवादल के पुनरुद्धार" और आगामी चुनावों की मजबूत नींव कह रही है। राहुल गांधी के पायलट प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने तीखा बयान देते हुए राहुल गांधी की कार्यशैली और सोच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "कभी आलू से सोना, कभी सोने से आलू—ऐसी सोच वाले व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है।" गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस को सेवा की समझ नहीं है और न ही दिल में सेवाभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ आरएसएस की काट के लिए सेवा कैंप और शिविरों की बात कर रही है, लेकिन सेवा समर्पण से होती है, योजनाओं और प्रयोगों से नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत आज इतनी खराब इसी सोच की वजह से है और आज पार्टी देश के केवल दो-तीन राज्यों में सिमटकर रह गई है। हालांकि, बीजेपी के इन बयानों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी को सेवादल की सेवा भावना समझ में ही नहीं आती। उन्होंने कहा, "सेवादल वर्षों से चुपचाप जनसेवा करता आ रहा है, बिना प्रचार-प्रसार के। अगर बीजेपी को उसकी गहराई समझनी हो, तो वह खुद एक बार किसी शिविर में आकर देख ले।"

मानक अग्रवाल ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी का पायलट प्रोजेक्ट न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि यह जनता से जुड़ने का नया तरीका है। उन्होंने कहा कि इस सेवा आधारित संपर्क मॉडल से कांग्रेस जमीन पर फिर से मजबूत होगी और 2028 के विधानसभा तथा 2029 के लोकसभा चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। कांग्रेस के इस पायलट प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें सेवादल के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर न केवल सेवा के कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि स्थानीय मुद्दों को समझने और समाधान सुझाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये सब कार्य बिना किसी राजनीतिक प्रचार के सेवा के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस मॉडल को कांग्रेस 'समर्पित जनसंपर्क' कह रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस का यह प्रयोग भले ही आरएसएस की तरह संगठित और दीर्घकालिक योजना न हो, लेकिन यदि सही तरीके से जमीन पर उतारा गया तो यह कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकता है। खासकर उस समय जब पार्टी को ज़मीनी स्तर पर दोबारा आत्मविश्वास और जनसमर्थन की आवश्यकता है। इस पूरी बहस में जो बात साफ़ तौर पर उभर रही है वह यह कि अब राजनीति सिर्फ नारे और भाषणों से नहीं, बल्कि ज़मीनी काम और जनसंपर्क की सशक्त रणनीति से जीती जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का सेवादल आधारित सेवा अभियान और भाजपा के आरएसएस पर आधारित सामाजिक संगठनात्मक तंत्र के बीच सीधी टक्कर की तस्वीर बनती जा रही है।

शहडोल में करोड़ों के गांजा मामले में थाना प्रभारी सस्पेंड, रिटायर्ड DFO के खेत से मिला 38 क्विंटल का बड़ा खेप

शहडोल। गांजा मामले ने पुलिस विभाग में भूचाल ला दिया है। इस मामले में करीब सवा तीन करोड़ रुपये मूल्य का 38 क्विंटल 36 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया गया था, जो रिटायर्ड डीएफओ के खेत में लावारिस हालत में मिला। इस गंभीर घटना की जांच के दौरान जयसिंहनगर थाना प्रभारी एसपी चतुर्वेदी की उदासीनता सामने आई, जिसके कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई को शहडोल के पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने आदेशित किया। गांजे की यह भारी खेप 121 बोरियों में थी, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 6 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा रिटायर्ड डीएफओ के खेत में पाया जाना पुलिस विभाग के लिए एक गंभीर चूक माना जा रहा है। इस मामले में न केवल गांजे की तस्करी की जांच की जा रही है, बल्कि यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इतने बड़े गांजा भंडार की जानकारी संबंधित थाने तक नहीं पहुंची। पुलिस की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि विभाग इस प्रकार की घटनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घटना से जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं और अधिकारियों को कड़ी सजा देकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का संदेश दिया गया है। यह मामला स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ हुई तेज- 23 दावेदारों के बीच वोटिंग और सदस्यता प्रक्रिया शुरू, सियासी घमासान ने लिया जोर

भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ अब और तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और दावों पर आपत्तियों के बाद अब वोटिंग और सदस्यता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में कुल 23 नाम सामने आए हैं, जिन्होंने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है। इन दावेदारों की सूची में कई बड़े नेताओं के परिजन भी शामिल हैं, जिससे इस चुनाव का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। युवा नेताओं के बीच यह जंग बेहद सघन और प्रतिस्पर्धात्मक है। टॉप तीन उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं के इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इस चुनावी घमासान में जबलपुर से पूर्व मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया, भोपाल से युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अभिषेक परमार, ग्वालियर से एनएसयूआई उपाध्यक्ष शिवराज यादव और देवास से विश्वजीत चौहान प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। ये युवा नेता बड़े-बड़े कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधकर

अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहे हैं और चुनाव में जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह हैं, जिन्हें यह जिम्मेदारी कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के पद छोड़ने के बाद सौंपी गई थी। विक्रांत भूरिया वर्तमान में कांग्रेस के आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यह चुनाव न केवल युवा कांग्रेस के भविष्य को तय करेगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में युवा नेताओं की भूमिका और उनकी प्रभावशीलता को भी परखने का अवसर होगा। आगामी वोटिंग प्रक्रिया और इंटरव्यू के परिणाम से ही यह स्पष्ट होगा कि युवा कांग्रेस के नए नेतृत्व के रूप में कौन सामने आएगा और प्रदेश की युवा राजनीति में किसका दबदबा होगा। इस बीच राजनीतिक हलकों में इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता और चर्चा बनी हुई है।